ब्रिक्स और डरबन शिखर सम्मेलन

2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व "ब्रिक" के नाम से जाना जाने वाला, ब्रिक्स समूह उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। रूस के अलावा इसके अन्य सदस्य नव-औद्योगिक देश हैं। विशाल, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इन देशों की विशिष्टता है और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव है।

ब्रिक्स देश संयुक्त रूप से विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 26 प्रतिशत और विश्व की जनसंख्या के 43 प्रतिशत भाग की हिस्सेदारी रखते हैं। यह समूह वैश्विक व्यापार के 17 प्रतिशत भाग को संचालित करता है और वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 11 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करता है। पांच राष्ट्रों का यह समूह खरीद शक्ति समतुल्यता के संदर्भ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत और वैश्विक सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग पांचवे भाग (19 प्रतिशत से अधिक) को संचालित करता है।

शिखर सम्मेलन- ब्रिक्स द्वारा वार्षिक शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिसमें सदस्य देश बारी-बारी से इसकी मेजबानी करते हैं-

शिखर सम्मेल	**वर्ष**	**मेजबान देश**	**स्थान**
पहला	2009	रूस	येकातेरिनबर्ग
दूसरा	2010	ब्राजील	ब्रासीलिया
तीसरा	2011	चीन	सान्या
चौथा	2012	भारत	नई दिल्ली
पांचवा	2013	दक्षिण अफ्रीका	डरबन

डरबन शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय

(1) नए विकास बैंक की स्थापना

वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार के लिए उठाए गए बड़े कदम के रूप में डरबन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में उभरती शक्तियों वाले पांच राष्ट्रों के इस समूह में अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के निधियन के लिए नए विकास बैंक की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई है।

अपर्याप्त दीर्घावधि निधियन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वजह से अवसंरचना विकास में विकासशील देश के समक्ष चुनौतियों की पृष्ठभूमि में इस कदम को देखा जा रहा है। ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों की गतिशीलता के संदर्भ में नए बैंक की स्थापना एक सही निर्णय है।

2...

ब्रिक्स बैंक का स्वागत करते हुए ब्रिक्स व्यापार मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने वाली फिक्की की अध्यक्ष श्रीमती नैना लाल किदवई ने कहा कि इससे ऋण सुविधाओं में वृद्धि होगी क्योंकि मौजूदा बैंक अकेले परियोजनाओं का निधियन नहीं कर सकते थे।

2. आकस्मिकता आरक्षित प्रबंध (सीआरए)

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में किसी प्रकार के वित्तीय संकट से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों ने 100 बिलियन डॉलर के आकस्मिकता आरक्षित प्रबंध के गठन का निर्णय लिया है। सीआरए का विचार दिल्ली में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा दिया गया था। इस बात पर सहमति हुई कि विशाल विनिमय वाला चीन 41 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा और भारत, ब्राजील और रूस प्रत्येक द्वारा 18 बिलियन डॉलर का योगदान किया जाएगा तथा दक्षिण अफ्रीका 5 बिलियन डॉलर का सहयोग देगा।

स्व-प्रबंधित सीआरए की स्थापना से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ब्रिक्स देशों को लघु-अवधि नकदी दबाब को दरकिनार कर सकेंगे और आपसी सहयोग तथा वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी।

3. ब्रिक्स व्यापार परिषद

पांच देशों के समूह के बीच वस्तु और सेवाओं के मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डरबन शिखर सम्मेलन में संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसमें सभी पांचों देशों से पांच-पांच सदस्य शामिल होंगे।

4. ब्रिक्स विचार-मंच परिषद

बहुपक्षीय संगठन को अभिनव विचारों से संचालित करने के लिए विचार मंच परिषद की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है।

संकलन- संपादक मंडल, रोजगार समाचार